

**बाबू लाल बनाम राहुल (न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया)  
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 1)**

---

**न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया के समक्ष**

**याचिकाकर्ता - बाबू लाल**

**बनाम**

**प्रतिवादी - राहुल**

**2022 का सीआर नंबर 3550**

**16 दिसंबर, 2022**

**हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली पर नियंत्रण) अधिनियम, 1973- धारा 13**

**(3) (ए) (आई) - प्रामाणिक आवश्यकता के आधार पर निष्कासन; कानून में**

**'कब्जे' और 'व्यवसाय' शब्द विनिमय नहीं हैं - महज कब्जे के बिना कब्जा धारा 13**

**(1) (ए) (आई) को अयोग्य घोषित नहीं करेगा - इसलिए गैर-मुकद्दमा वाले मकान**

**मालिक के लिए केवल कब्जा पर्याप्त नहीं है - प्रामाणिकता स्थापित करने की**

**आवश्यकता है - निष्कासन की अनुमति है।**

**बाबू लाल बनाम राहुल (न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया)  
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 2)**

सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के अधिनियम की धारा 13 (2) (वी) के प्रावधानों के संदर्भ में राम दास बनाम दर्विंदर (2004) 3 एससीसी 684 में 'अधिकार' और 'कब्जा' शब्दों की व्याख्या की। यह मामला एक मकान मालिक से संबंधित है, जिसने इस आधार पर किराएदार के परिसर का कब्जा मांगा था कि किराएदार ने उचित कारण के बिना चार महीने की लगातार अवधि के लिए उस पर कब्जा करना बंद कर दिया था।

(अनुच्छेद 11.5)

याचिकाकर्ता की ओर से वकील अमन बाहरी।

कैविएटर के लिए वकील मुनीश गुप्ता।

**न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया (मौखिक)**

(1) यह किराया नियंत्रक द्वारा पारित 20.8.2018 के निष्कासन के आदेश के खिलाफ किरायेदार की पुनरीक्षण याचिका है, और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित 16.5.2022 का आदेश, निष्कासन आदेश की पुष्टि करता है।

**बाबू लाल बनाम राहुल (न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया)  
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 3)**

(2) प्रतिवादी/मकान मालिक ने हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली पर नियंत्रण) अधिनियम, 1973 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 13 के तहत याचिकाकर्ता/किरायेदार को पुल बाज़ार, नारनौल में स्थित उसकी दुकान से तीन आधारों पर निकालने के लिए आवेदन/याचिका दायर की, अर्थात्; (i) किराए की बकाया राशि का भुगतान न करना, (ii) मकान मालिक द्वारा अपना कार्यालय, कार्यशाला और प्रशिक्षण कक्ष चलाने के लिए परिसर की वास्तविक आवश्यकता और आवश्यकता, और (iii) परिसर अपनी जीर्ण-शीर्ण स्थिति के कारण मानव निवास के लिए अनुपयुक्त होना। रेंट कंट्रोलर के आदेशानुसार उपरोक्त सभी तीन आधारों के तहत याचिकाकर्ता/मकान मालिक को पट्टान्तरित (नष्ट हो चुके) परिसर से बेदखल करना है। अपीलीय प्राधिकरण ने हालांकि माना कि किराए की बकाया राशि का भुगतान न करने का आधार मकान मालिक के पास उपलब्ध नहीं था, और शेष दो आधारों पर परिसर की वास्तविक आवश्यकता और जीर्ण-शीर्ण स्थिति के आधार पर बेदखली का आदेश दिया।

(3) निष्कासन को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि निर्माण विशेषज्ञ रिपोर्ट एक्स.पीडब्ल्यू 2/बी के साथ-साथ उसके साथ संलग्न

**बाबू लाल बनाम राहुल (न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया)  
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 4)**

तस्वीरों के आधार पर पट्टान्तरित परिसर की जीर्ण-शीर्ण स्थिति स्थापित की गई है, हालांकि इस भवन विशेषज्ञ ने खुद को क्रॉस-एग्जामिनेशन के अधीन नहीं किया था। इसलिए, उनके साक्ष्य, सवालों के घेरे में रिपोर्ट इन तस्वीरों को इस आधार पर खाली कराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था ताकि ध्वस्त परिसर की जर्जर स्थिति का पता लगाया जा सके या उन्हें खाली कराने का आदेश दिया जा सके। प्रतिवादी/कैविएटर/मकान मालिक के वकील इस बात पर विवाद नहीं कर सकते थे कि गवाह को जिरह का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए, पीडब्ल्यू -2 की गवाही के साथ-साथ उनकी रिपोर्ट को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है, और नीचे दिए गए दोनों प्राधिकरणों के निष्कर्षों को समाप्त परिसर की जीर्ण-शीर्ण स्थिति के आधार पर किराएदार को बेदखल करने का आदेश दिया गया है।

(4) याचिकाकर्ता/किराएदार के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी/मकान मालिक ने निष्कासन याचिका में झूठे बयान दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि वह संबंधित शहरी क्षेत्र में किसी अन्य परिसर पर कब्जा नहीं कर रहा था। इस संबंध में उन्होंने दिनांक 26.3.2015 के एक पंजीकृत हस्तांतरण विलेख, अनुबंध ए-1 का उल्लेख किया है, जिसके तहत मकान मालिक के पिता सुरेंद्र कुमार ने 9.10.2015

**बाबू लाल बनाम राहुल (न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया)**  
**आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 5)**

को निष्कासन याचिका दायर करने से पहले नारनौल के ब्रिज मार्केट की पुरानी आबादी के लालडोरा के भीतर स्थित एक दुकान/संपत्ति को मकान मालिक के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया था और उन्हें उसी बाजार में स्थित संपत्ति का स्वामित्व और कब्जा दिया जहां पट्टान्तरित परिसर मौजूद था। 26.3.2015 के इस स्थानांतरण विलेख को अतिरिक्त सबूत के रूप में रिकॉर्ड में लाने के लिए 2022 का सीएम 10931-सीआईआई नामक एक आवेदन दायर किया गया है। वकील ने प्रतिवादी/मकान मालिक-पीडब्ल्यू 1, अनुबंध-पी/5 से जिरह का भी हवाला दिया है, जहां उन्होंने किसी अन्य वाणिज्यिक संपत्ति के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त करके जानबूझकर इस तथ्य को छिपाया। निष्कासन आवेदन/याचिका 09.10.2015 को दायर की गई थी और स्थानांतरण विलेख दिनांक 26.3.2015 है। इसलिए, मकान मालिक दूसरी दुकान पर कब्जा करने के भौतिक तथ्य को छिपाने का दोषी है, और उसकी बेदखली याचिका उस आधार पर खारिज कर दी जानी चाहिए। अपनी दलील के समर्थन में, उन्होंने **बांके राम बनाम श्रीमती सरस्वती देवी और अन्य<sup>1</sup>** में और इस न्यायालय द्वारा **शंकर लाल बनाम**

---

<sup>1</sup> 1977 (1) सी आर सी (Rent) 595

**बाबू लाल बनाम राहुल (न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया)  
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 6)**

मदन लाल और अन्य<sup>2</sup> के मामले में पारित एक और निर्णय इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया है।

(5) प्रतिवादी/मकान मालिक के विद्वान वकील ने कहा कि मकान मालिक द्वारा किसी भी प्रासंगिक तथ्य को छिपाया नहीं गया था, और वह संबंधित शहरी क्षेत्र में किसी अन्य परिसर या दुकान के कब्जे में नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि संबंधित परिसर को मकान मालिक द्वारा अपने व्यवसाय और कार्यालय का विस्तार करने के लिए आवश्यक था, और इस तथ्य को निष्कासन याचिका में विधिवत रूप से प्रस्तुत किया गया है। जहां तक दिनांक 26.3.2015 के स्थानांतरण विलेख का संबंध है, इसे किराया नियंत्रक या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यहां तक कि हस्तांतरण विलेख (लिखित कानूनी दस्तावेज) में उल्लिखित दुकान भी मकान मालिक के कब्जे में नहीं है।

(6) पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना गया है।

---

<sup>2</sup> 2011 (1) सी आर सी (Rent) 139

**बाबू लाल बनाम राहुल (न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया)  
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 7)**

(7) दिए गए तर्कों पर विचार करने के लिए, अधिनियम की धारा 13 को संदर्भित करना उचित है, जो निम्नानुसार है:

1 1977 (1) आर.सी.आर (किराया) 595

2 2011 (1) आर.सी.आर (किराया) 139

13. किरायेदारों की बेदखली:

(1) XXX XXX

(2) XXX XXX XXX

(3) एक मकान मालिक नियंत्रक को एक आदेश के लिए आवेदन कर सकता है जिसमें किराएदार को मकान मालिक को कब्जा में रखने का निर्देश दिया गया हो-

(क) आवासीय भवन के मामले में, यदि-

(i) वह अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए इसकी आवश्यकता रखता है, संबंधित शहरी क्षेत्र में किसी अन्य आवासीय भवन पर कब्जा नहीं कर रहा है और उक्त शहरी क्षेत्र में

**बाबू लाल बनाम राहुल (न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया)  
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 8)**

1949 के अधिनियम के लागू होने के बाद पर्याप्त कारण के बिना ऐसी इमारत को खाली नहीं किया है।

(8) इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि स्थापित कानून के अनुसार मकान मालिक द्वारा परिसर की वास्तविक व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर मकान मालिक द्वारा गैर-आवासीय निर्माण से भी अधिनियम की धारा 13 (3) (ए) (आई) के प्रावधानों के तहत बेदखल करने की मांग की जा सकती है।

(9) इस मामले में, व्यक्तिगत आवश्यकता पर आधार का उल्लेख करने के लिए, मकान मालिक ने इस दलील पर परिसर से बेदखली की मांग की है कि वह कार्यालय, कार्यशाला के लिए जगह की कमी का सामना कर रहा है और प्रशिक्षण कक्ष और ग्राहकों और कर्मचारियों से निपटने के लिए तथा उसके पास इस उद्देश्य के लिए कोई अन्य उपयुक्त स्थान नहीं है। वह वर्तमान किराएदार परिसर और बगल की दुकान की साइट का पुनर्निर्माण करके अपनी कार्यशाला और प्रशिक्षण कक्ष से अलग एक कार्यालय बनाना चाहते हैं, जो नितिन के साथ संयुक्त रूप से उनके स्वामित्व में है। इसलिए, किराएदार को विचाराधीन परिसर को खाली करने की आवश्यकता है। शहरी



**बाबू लाल बनाम राहुल (न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया)  
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 9)**

क्षेत्र नारनूल में मकान मालिक के पास अपना कार्यालय, कार्यशाला और प्रशिक्षण कक्ष स्थापित करने के लिए कोई अन्य उपयुक्त परिसर उपलब्ध नहीं है।

(10) दोनों अधिकारियों ने समवर्ती रूप से मकान मालिक की आवश्यकता को प्रामाणिक माना है और यह कि उसने किसी भी वैकल्पिक आवास के बारे में कोई भौतिक तथ्य नहीं छिपाया है। रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है, न ही याचिकाकर्ता/किरायेदार के विद्वान वकील द्वारा कोई इंगित किया जा सकता है, कि व्यवसाय के विस्तार के लिए मकान मालिक की परिसर की आवश्यकता वास्तविक नहीं है।

(11) संबंधित शहरी क्षेत्र में एक अन्य दुकान का स्वामित्व और कब्जा मकान मालिक को देने वाले दिनांक 26.3.2015 के हस्तांतरण विलेख को कथित रूप से छिपाने के कारण इस न्यायालय के समक्ष किराया याचिका को खारिज करने की मांग की गई है। दलील यह है कि अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) (आई) के अनुसार तथ्यों को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था, जो मकान मालिक निर्विवाद रूप से करने में विफल रहा।

**बाबू लाल बनाम राहुल (न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया)**  
**आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 10)**

(11.1) किसी दुकान/संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे से संबंधित दिनांक 26.3.2015 के हस्तांतरण विलेख में अभिलेखों का संदर्भ देना उचित है, जिसके आधार पर मकान मालिक के खिलाफ धारा 13 (1) (ए) (आई) को छिपाने और गैर-अनुपालन की दलील दी गई है। विलेख का अंतिम पैराग्राफ निम्नानुसार है:

इसलिए, 97.96 वर्ग गज की संपत्ति और 3526.56 वर्ग फुट के कुल कवर क्षेत्र के संबंध में स्वामित्व और कब्जे के हस्तांतरण को लिखित रूप में लिखा गया है ताकि यह प्राधिकरण के रूप में काम कर सके।

(11.2) ये हस्तांतरण विलेख में औपचारिक पाठ हैं, जो मकान मालिक को संपत्ति / दुकान के स्वामित्व और कब्जे के हस्तांतरण को दर्ज करते हैं। मकान मालिक से यह सवाल अपने आप में, कब्जे की डिलीवरी पर अंतिम शब्द नहीं हैं और विवाद की स्थिति में, कब्जे की डिलीवरी को विश्वसनीय प्रमाणों द्वारा तथ्य के रूप में साबित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, भले ही विवरण को स्वामित्व और कब्जे के हस्तांतरण के तथ्य को स्थापित करने के लिए लिया जाता है पर यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त

**बाबू लाल बनाम राहुल (न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया)**  
**आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 11)**

हस्तांतरण के अनुसार संपत्ति/दुकान बेदखली याचिका दायर होने तक प्रतिवादी/मकान मालिक के 'कब्जे' में रही। कानून की आवश्यकता है, 'कब्जा' न कि 'स्वामित्व और कब्जा'।

(11.3) अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) (आई) में तीन शर्तों की आवश्यकता है; (i) मकान मालिक को अपने स्वयं के पेशे के लिए परिसर की आवश्यकता होती है, (ii) वह संबंधित शहरी क्षेत्र में किसी अन्य आवासीय भवन पर कब्जा नहीं कर रहा है, (iii) उसने उक्त शहरी क्षेत्र में 1949 के अधिनियम के लागू होने के बाद पर्याप्त कारण के बिना ऐसी इमारत खाली नहीं की है। हम केवल दूसरी शर्त से संबंधित हैं, जिसमें प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'कब्जा' है, अर्थात्, 'पेशे में'। 'आधिपत्य' और 'कब्जा' शब्द अलग-अलग अर्थों के साथ दो अलग-अलग शब्द हैं; विधायिका ने जानबूझकर केवल उत्तरार्द्ध का उपयोग किया है। अधिनियम की धारा 13 (3) में 'कब्जे' शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन धारा 13 (3) (ए) (आई) 'आधिपत्य/कब्जे की ताकत' शब्द का उपयोग करती है। इसलिए, दोनों का उपयोग अंतर-परिवर्तनशील रूप से नहीं किया जा सकता है। किसी के पास संपत्ति हो सकती है, लेकिन उस पर कब्जा नहीं हो सकता है। 'पेशे' शब्द का अर्थ है, 'पेशे में परिसर का उपयोग'। यह नियंत्रण में होने और परिसर का उपयोग करने

**बाबू लाल बनाम राहुल (न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया)**  
**आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 12)**

की स्थिति को संदर्भित करता है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी, दसवें संस्करण- पृष्ठ संख्या 1248 और 1351 में क्रमशः 'आधिपत्य' और 'कब्जा' शब्दों को सौंपा गया अर्थ भी उनके अलग-अलग होने की ओर इशारा करता है, जिनके अलग-अलग निहितार्थ हैं। यह निम्नानुसार है:

**आधिपत्य 2. अचल संपत्ति का कब्जा, नियंत्रण या उपयोग; अधिभोग।**

**कब्जा 1. किसी की शक्ति में संपत्ति रखने या रखने का तथ्य; संपत्ति पर प्रभुत्व का प्रयोग।**

(11.4) इसलिए, 'आधिपत्य' का एक व्यापक अर्थ है क्योंकि इसमें नियंत्रण में होने या संपत्ति का उपयोग करने के अलावा कब्जा शामिल है, लेकिन इसके विपरीत नहीं। 'कब्जा' में आधिपत्य शामिल नहीं है; यह दूसरों के बहिष्करण के लिए एक संपत्ति पर नियंत्रण में होने की स्थिति को संदर्भित करता है, जो उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा वास्तविक उपयोग में नहीं हो सकता है।

**बाबू लाल बनाम राहुल (न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया)**  
**आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 13)**

(11.5) सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के अधिनियम की धारा 13 (2) (वी) के प्रावधानों के संदर्भ में **राम दास बनाम दर्विंदर<sup>3</sup>** में 'आधिपत्य' और 'कब्जा' शब्दों की व्याख्या की। यह मामला एक मकान मालिक से संबंधित है, जिसने इस आधार पर किरायेदार के परिसर का कब्जा मांगा था कि किरायेदार ने उचित कारण के बिना चार महीने की लगातार अवधि के लिए उस पर कब्जा करना बंद कर दिया था। उस संदर्भ में इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

7. "आधिपत्य" और "कब्जा" शब्द आम बोलचाल में परस्पर उपयोग किए जाते हैं। हालांकि, कानून में, किसी संपत्ति पर कब्जा उसे मालिक के रूप में रखने के बराबर हो सकता है, लेकिन कब्जा करना इसमें मौजूद होकर कब्जा रखना है। किराया नियंत्रण विधान आवास की कमी का परिणाम हैं। विभिन्न राज्यों में लागू अधिकांश किराया नियंत्रण कानून, किराएदार से किराएदारी परिसर पर कब्जा करने की उम्मीद करते हैं। यदि वह स्वयं कब्जा करना बंद कर देता है और किसी और के पक्ष में कब्जे के साथ भाग लेता है, तो यह निष्कासन के लिए एक आधार प्रदान करता है। इसी तरह, कुछ कानून इसे बेदखली के आधार के रूप में प्रदान करते हैं यदि किराएदार ने किराएदारी

---

<sup>3</sup> 2004 (3) एस सी सी 684

## बाबू लाल बनाम राहुल (न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 14)

परिसर पर कब्जा करना बंद कर दिया है, हालांकि उसने उस पर कब्जा बनाए रखा हो। हरियाणा अधिनियम की योजना किरायेदार को परिसर के कब्जे में रहने पर जोर देने के लिए भी है। किराएदार से अपेक्षा की जाती है कि वह संपत्ति का उपयोगी उपयोग करे और किरायेदारी परिसर को वास्तव में वहां रहकर किसी भी अनुमेय और उपयोगी गतिविधि के अधीन करे। मकान मालिक की इस दलील का कि किरायेदार ने परिसर पर कब्जा करना बंद कर दिया है, यह कोई जवाब नहीं है कि किरायेदार को किरायेदारी परिसर पर कब्जा करने का अधिकार है और वह उसके न्यायिक कब्जे में है...

'आधिपत्य' और 'कब्जा' शब्दों को साँपे गए इस अर्थ का तत्काल याचिका में उठने वाले मुद्दे से सीधा संबंध है, क्योंकि राम दास (पूर्व) मामले में भी परिसर का कब्जा या कब्जा मुद्दा था।

(11.6) अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) (आई) की आवश्यकता यह है कि मकान मालिक संबंधित शहरी क्षेत्र में किसी अन्य आवासीय/ गैर-आवासीय भवन पर कब्जा नहीं कर रहा है, अर्थात्, वह परिसर का कब्जा नहीं रख रहा है और इसमें उपस्थित होकर भी इसका उपयोग कर रहा है। मकान मालिक द्वारा किसी परिसर के स्वामित्व और कब्जे,

**बाबू लाल बनाम राहुल (न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया)**  
**आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 15)**

बिना उसके कब्जे के, कोई परिणाम नहीं होगा और एक मकान मालिक को वास्तविक व्यक्तिगत उपयोग के लिए इसके कब्जे की मांग करने से नहीं रोका जा सकता है।

(12) संबंधित शहरी क्षेत्र में किसी अन्य उपयुक्त परिसर पर मकान मालिक का कब्जा नहीं होने के तथ्य को निष्कासन याचिका में दलील दी गई थी और साक्ष्य में भी साबित किया गया था। मकान मालिक द्वारा प्रारंभिक बोझ का निर्वहन किया गया है; किराएदार पर यह स्थापित करने की जिम्मेदारी थी कि पूर्व एक अन्य आवासीय / गैर-आवासीय इमारत के कब्जे में था। हालांकि, वह ऐसा करने में विफल रहे। अब, इस न्यायालय के समक्ष, दिनांक 26.3.2015 के हस्तांतरण विलेख पर भरोसा करके और दुकान के स्वामित्व और कब्जे के बारे में उसके अभिलेखों का उल्लेख करके, कोई दलील नहीं दी जा सकती है कि मकान मालिक संबंधित शहरी क्षेत्र में किसी अन्य गैर-आवासीय संपत्ति / दुकान के कब्जे में था; और यह तथ्य था कि निष्कासन याचिका दायर करते समय उन्होंने इसे छिपाया। हस्तांतरण विलेख प्रथम दृष्टया यह भी स्थापित नहीं करता है कि मकान मालिक उसमें उल्लिखित संपत्ति / दुकान के कब्जे में था। इसलिए, हस्तांतरण विलेख को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लाने के लिए

**बाबू लाल बनाम राहुल (न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया)**  
**आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 16)**

आवेदन, और साथ ही उस पर आधारित तथ्यों को छिपाने की दलील भी आधारहीन है।

(13) इसके अलावा, बांके राम मामले (पूर्व) और शंकर लाल मामले (पूर्व) में इस न्यायालय के निर्णयों पर किराएदार के विद्वान वकील द्वारा की गई निर्भरता भी गलत है। फैसले इस आशय के हैं कि मकान मालिक को यह साबित करने की आवश्यकता है कि वह शहरी क्षेत्र में किसी अन्य इमारत पर कब्जा नहीं कर रहा है। यह, वास्तव में, यहां मकान मालिक द्वारा किया गया है और, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उस कारण से उसकी ओर से कोई छिपाव नहीं है।

(14) उपरोक्त विश्लेषण के मद्देनजर, याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। परिसर की जीर्ण-शीर्ण स्थिति के आधार पर बेदखली का आदेश देने वाले प्राधिकारियों के निष्कर्षों को निरस्त कर दिया जाता है और परिसर की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली का आदेश देने वाले निष्कर्षों को बरकरार रखा जाता है। तदनुसार, निष्कासन आवेदन/याचिका की अनुमति दी जाती है।

दिव्य सरूप



**बाबू लाल बनाम राहुल (न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया)  
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2003 (2) (पृष्ठ 17)**

**अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

**अंकिता महाजन**

**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**

**(Trainee Judicial Officer)**

**कैथल, हरियाणा**